1	2		3
36.	परामर्शदायी सेवाएं		
	डिजाइन तथा इंजीनियरी सेवाएं		21.78
	प्रबन्ध सेवाएं		9.24
	विपणन		2.61
	निर्माण		4.25
	अन्य (परामर्शदायी सेवाएं)		4.04
		योग:	41.92
37.	सेवा क्षेत्र		
	वित्तीय		1488.70
	गैर-वित्तीय सेवाएं		862.87
	बैंकिंग सेवाएं		82.33
	अन्य सेवाएं		13.11
		योग:	2447.01
38.	होटल तथा पर्यटन		
	होटल तथा रेस्तरां		1109.26
	पर्यटन		1.67
		योग:	1110.93
39.	ट्रेडिंग कंपनी		67.86
40.	विविध उद्योग		
	बागवानी		12.56
	कृषि		24.20
	पुष्पखेती		32.32
	अन्य (विविध उद्योग)		720.57
		योग:	789.65
		योग:	27929.16

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

2743. श्री अजीत जोगी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का नया निवेश करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाभ में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र का कोई नया उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मौजूदा उपक्रमों में आधुनिकीकरण/ विस्तार/विविधी-करण सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए नए सिरे से निवेश का अनुमोदन किया है।

(ग) सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में किए गए उपायों में सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, प्रशासनिक मन्त्रालयों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कार्य-निष्पादन समीक्षा के लिए आवधिक बैठकें करना, निदेशक मण्डलों को और अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करना और उनका व्यवसायीकरण करना, प्रौद्योगिकी उन्नत करना, उत्पाद मिश्र, संयुक्त उद्यमों का अनुमोदन करना इत्यादि शामिल हैं।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण

2744. **श्री अजीत जोगी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारी घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन उद्यमों का निजीकरण करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें लाभकारी बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) 31-3-1994 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की राज्यवार सूची 22-3-1995 को सभा पटल पर प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1993-94 के खण्ड-I के परिशिष्ट III में दी गई है। वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 117 उद्यमों ने घाटा उठाया है जिसका ब्यौरा सर्वेक्षण के उपर्युक्त खण्ड के विवरण सं० 7ख में दिया गया है।

(ख) अब तक इन उद्यमों में से किसी उद्यम के निजीकरण का निर्णय नहीं किया गया है;

(ग) सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन में सुधार